International Journal of Applied Research 2021; 7(10): 74-76

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(10): 74-76
www.allresearchjournal.com
Received: 07-08-2021
Accepted: 09-09-2021

धनंजय कुमार
शोध छात्र, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत

Corresponding Author:
धनंजय कुमार
शोध छात्र, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत

स्वच्छ भारत मिशन

धनंजय कुमार

प्रस्तावना

15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने लालकिले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए गंदगी और खुले में शौच के खिलाफ बिगुल बजाया। 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ और खुले में शौचमुक्त भारत बनाने का आह्वान किया। 2 अक्टूबर 2019 की तारीख का विशेष महत्व है। इस दिन महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती है।

स्वच्छता एक राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप ले चुका है। इस आन्दोलन के पीछे महज साफ–सफाई की इच्छा ही नहीं है बल्कि स्वच्छता के इस मुद्दे के गंभीर सामाजिक–आर्थिक निहितार्थ हैं।

विश्व बैंक के एक आंकलन के अनुसार भारत में लगभग 40 प्रतिशत बच्चे शारीरिक रूप से अविकसित हैं। कई घातक रोगों से ये पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण अस्वच्छता को बताया गया है। अस्वच्छता के कारण देश को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आने वाली पीढ़ियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि देश को पूर्ण सक्षम कार्यबल नहीं प्राप्त हो पाता है।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बच्चों की शारीरिक विकास का रूकना एक बड़ी समस्या है। शारीरिक वृद्धि के रूक जाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या खड़ी होती है। खुले में शौच के कारण कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियां गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डालती है। साफ–सफाई की कमी के कारण ऐसे परिवार के लोग बीमारी के गिरफ्त में आते हैं।

पानी और स्वच्छता से संबंधित बीमारियां पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। हमारे यहां बाल मृत्यु दर 53 प्रति हजार जीवित प्रसव हैं। बीमारी फैलाने वाले जीवाणु के संक्रमण से पेचिश जैसी बीमारियां फैलती हैं। इसके प्रकोप से शरीर के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। परिणामस्वरूप कुपोषण, शारीरिक वृद्धि का रूकना और कभी–कभी मृत्यु जैसी भी घटना का साक्षात्कार करना पड़ता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल साफ पानी मिले और स्वच्छता जैसी सुविधाएं प्राप्त हो जाय तो बीमारियां फैलाने वाले जीवाणुओं से संपर्क का खतरा कम हो जायेगा। दस्त एवं पेचिश जैसी बीमारियों की आशंका कम हो जाती है।

भारत को स्वच्छ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है 60 करोड लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलना। खुले में शौच मानव सभ्यता के आरंभ से ही जारी है। भारत में सदियों तक यह लाखों लोगों की जीवनशैली का हिस्सा रहा है। अतएव स्वच्छता को केवल सरकार या सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं मानकर सभी की जिम्मेदारी बनाने की जरूरत है। इसे जन–आन्दोलन का रूप देना होगा। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छाग्रह ने राष्ट्र को बिल्कुल उसी तरह प्रभावित किया है जैसे महात्मा गांधी का सत्याग्रह आन्दोलन।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत साफ–सफाई और स्वास्थ्य के बारे में लोगों की अपनी–अपनी सोंच और धारणाएं होती है। शौचालय को अपवित्र प्रदूषण का स्त्रोत मानते हैं। खुले में शौच की आदत ने घरों में शौचालयों के निर्माण के प्रति लोगों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया जिन लोगों ने शौचालयों का निर्माण करा भी लिया तो उनकी खुले में शौच की आदत नहीं छूट पायी। घर के पुरूषों का सुबह के समय घुमने के लिए खेतों में निकलना और खुले में शौच करना आदत का हिस्सा बन चुका था जिसे छुड़ाना और उन्हें शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना बड़ा कठिन कार्य था। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्या यह है कि ये शौचालय के लिए कर्ज नहीं ले सकते हैं। इसे अतिरिक्त आर्थिक बोझ समझते हैं।

स्वच्छ भारत अभियान के कारण राज्यों में निर्मल भारत के साथ मर्यादा अभियान एवं अन्य योजनाएं चलाई जा रही है। मर्यादा अभियान नाम देकर मध्यप्रदेश सरकार ने स्वच्छता अभियान को महिलाओं

की इज्जत के साथ जोड़कर प्रचारित किया है। इसका प्रभाव लोगों पर स्पष्टतः देखा जा सकता है। लोग इस बात से सहमत दिखे कि महिलाओं का खुले में शौच जाना उनकी मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन मर्यादा अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर है कि गांवों में पानी की उपलब्धता किस हद तक है। अतः मर्यादा अभियान इस बात के लिए प्रेरित करती है कि लोग शौचालय बनवाएं और मर्यादापूर्ण एवं स्वस्थ तरीके से जिने की कोशिश करें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में शहंशाहपुर गांव में दोहरे गड्ढे वाले शौचालय के निर्माण के लिए श्रमदान किया। उन्होंने गांव को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लेने वाले लोगों के साथ बातचीत की। मोदी ने शौचालय को 'इज्जत घर' नाम दिए जाने की सराहना की है।

प्रधानमंत्री का विजन और जुनून एक जन–आन्दोलन में बदल गया है। देश के मंत्रियों, सांसदों, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारियों, मशहूर हस्तियों, कॉरपोरेट स्थानीय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों, गैर–सरकारी संगठनों, छात्रों और नागरिक समाज, संगठनों सभी ने बढ़–चढ़कर श्रमदान किया और पूरे देश में एक सकारात्मक उर्जा का संचार हुआ है।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय निर्यामत रूप से सफाई अभियानों का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री और राज्यों ने स्वच्छता मिशन और व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार अभियान आयोजित किए गए हैं।

टेलीविजन, रेडियो माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन, विद्यााबालन, शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा, अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर को इस अभियान से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जाने–माने लोगों और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को भी अभियान में सहयोगी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। कार्पोरेट घराने, सिविल सोसाइटी संगठन और अन्य मंत्रालय व विभाग भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनता में साफ–सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद को आगे आए हैं।

नमामि गंगे अभियान के तहत पांच राज्यों– उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 52 जिलों में गंगा नदी के तट पर बसे 4480 गांवों को खुले में शौच की आदत से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 30 मई, 2017 से 'दरवाजा बंद' नाम का एक प्रचार अभियान शुरू किया है।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है खासतौर पर यह महिला अधिकार संपन्नता की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है और वह दिन दूर नहीं जब घूंघट काढ़े, किसी नवविवाहिता को खुले में शौच जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। किसी किशोरी का स्कूल वहां शौचालय नहीं होने की वजह से छुड़वा नहीं दिया जायेगा।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इस प्रचार अभियान का शुभारंभ जाने–माने फिल्मी सितारे अभिताभ बच्चन, केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव और केन्द्र तथा राज्य के कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मुंबई में किया गया। राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों और कुछ चुनी हुई ग्राम पंचायतों के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। इस अभियान को विश्व बैंक का सहयोग मिल रहा है और शुभारंभ के बाद इसे देशभर में चलाया जा रहा है। यह अभियान ऐसे लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के मकसद से चलाया जा रहा है जिनके घरों में शौचालय तो हैं मगर वे उनका इस्तेमाल नहीं करते। इस अभियान में फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की भी भागीदारी है जिन्हें ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सामने आने और अभियान का नेतृत्व करने को कहा जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में निवेश का फायदा देखने को मिला। इसके अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों के लिए अपने स्थानीय नेताओं द्वारा जारी निर्देशों को समझना ज्यादा आसान था। देश को बदलने से जुड़े प्रयासों में इस पहलू को शामिल किया गया है। हाल में 10 करोड़ परिवारों तक स्वच्छता को पहुंचाने के लक्ष्य से लेकर कार्यक्रम के अगले चरण की अवधि के दौरान स्थानीय पंचायत की भूमिका पर जोर दिया गया। नए चरण में न सिर्फ उन घरों तक पहुंचने की जरूरत है, जहां शौचालय नहीं है, बल्कि इसमें मौजूदा शौचालयों के रखरखाव और उसे सुरक्षित बनाए रखने और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा इसके इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए व्यवहार संबंधी बदलाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने की खातिर निवेश जारी रखने और स्वच्छता के अगले चरण में निवेश में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। साल 2018 में सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधी दिशा–निर्देश 2018 में संशोधन किया। इसमें विशेष तौर पर कहा गया कि 'स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, पेयजल को राज्य स्तर पर संशोधित ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधी दिशा–निर्देश में प्राथकिमता देने की जरूरत है।

नया चरण शुरू करने के उद्देश्य से सरकार ने सितंबर 2019 में 10 साल के लिए ग्रामीण स्वच्छता रणनीति का मसौदा जारी किया। इसमें स्वच्छता का बेहतर स्तर बनाए रखने और इसमें और बढ़ोतरी के लिए 2029 तक उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया गया है। इस रणनीति का मकसद खुले में शौच से मुक्ति के सिलसिले को बनाए रखने के लिए केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित पक्षों को नियोजन के लिए दिशा–निर्देश मुहैया कराना है। रणनीति के मुताबिक, खुले में शौच से मुक्ति के सिलसिले को बनाए रखना और हर गांव के पास ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की सुविधा सुनिश्चित करना है। भारत इस दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजे)–6, खासतौर पर 6.2 का लक्ष्य हासिल करने के लिए यह जरूरी है। एसडीजे 6.2 के लक्ष्य के मुताबिक, साल 2020 तक सबको पर्याप्त और बराबर स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराना, खुले में शौच के चलन को खत्म करना, महिलाओं, लड़कियों और अन्य वंचितों पर विशेष ध्यान देना शामिल है।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वच्छ भारत ग्रामीण की उपलब्धियों को बरकरार रखना, देश के सभी गांववासियों के लिए स्वच्छता का सुरक्षित प्रबंधन और ठोस कचरा प्रबंधन के द्वारा साफ–सुथरा पर्यावरण का लक्ष्य हासिल करना है।

नई प्रणाली में ग्राम पंचायतों को रणनीतिक तौर पर गांवों में हो रहे ठोस और तरल कचरा प्रबंधन संबंधी प्रणाली के केन्द्र में रखा गया है। इसमे कहा गया है कि निर्णय हमेशा यथासंभव निचले स्तर पर लिए जाने चाहिए, जहां वे ज्यादा प्रभावी होंगे। 'विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली और संस्थागत ढांचा' अध्याय में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में कहा गया है। इसमें स्वच्छाग्रहियों के उन्नयन और प्रशिक्षण की भी बात कही गई है, ताकि वे पानी और स्वच्छता को लेकर अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में जान सके और जरूरी सेवाओं के लिए प्रबंधन प्रणाली तैयार कर सकें। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से सभी संबंधित पक्ष अलग–अलग मंत्रालयों और विभागों को थोड़ी–थोड़ी जिम्मेदारी बांटकर निवेश और काम को रफ्तार दे सकते हैं। सभी पक्षों को नियमित रूप से एक–दूसरे से संपर्क में रहना चाहिए। उन्हें विकास की प्रक्रिया से जुड़े साझीदारों मसलन निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटी संगठनों और अकादमिक संस्थानों को जरूरत के हिसाब से शामिल करना चाहिए।

शहरी क्षेत्र कचरा ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने और उसका इस्तेमाल करने में सक्षम है। लेकिन ग्रामीण समुदायों को स्थानीय स्तर पर टिकाऊ विकल्पों को पेश करना जरूरी है। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर बेहतर ढंग से काम हो सकता है। कचरा प्रबंधन और संसाधनों की रीसाइक्लिंग संबंधी कोशिशों के लिए यही बात लागू होती है। इसमें ठोस कचरा प्रबंधन का मामला भी शामिल है। इसके अलावा, प्रधान/सरपंच, स्वच्छाग्रही और जमीनी स्तर अन्य अहम लोगों की भूमिका और उनके प्रभाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सेवाओं को प्रासंगिक, असरदार और टिकाऊ बनाने के लिए उनसे जुड़ी संभावनाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही, समुदाय से जुड़े नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी जरूरत है।

इसके अलावा, जल जीवन मिशन की शुरूआत की गई है, जिसका लक्ष्य 2024 तक सभी घरों में पीने का पानी मुहैया कराना है। स्वच्छता कार्यक्रम से जल आपूर्ति अभियान को जोड़ना जरूरी है। इससे पानी के संसाधन सुरक्षित रह सकेंगे और स्वच्छता सेवाएं भी जारी रहेंगी। जिला और राज्य स्तर के नेता मौखिक रूप से संमिलन की वकालत कर सकते हैं, लेकिन असली कोशिश ग्राम पंचायतों को ही करनी होगी, जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के तहत फंड और बाकी चीजें मुहैया कराई जाती है।

नई रणनीति के तहत तय फॉर्मूले को लागू करने के लिए सरकार (जल शक्ति मंत्रालय) पहले ही व्यावहारिक कदम उठा चुका है। ये कदम स्वच्छ भारत मिशन की मौजूदा रणनीति से ओडीएफ प्लस की तरफ बढ़ने के दौरान उठाए गए हैं। यूनिसेफ की मदद से केन्द्र सरकार द्वारा देश के सभी ग्रामीण इलाकों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू की गई है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत के प्रधान समेत पंचायत के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों की अहम भूमिका पर जोर दिया गया है। इस अभियान का लक्ष्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण मॉडल का इस्तेमाल कर तकरीबन 258000 ग्राम पंचायतों तक (तकरीबन 774000 व्यक्ति) पहुंचना है। केन्द्र सरकार और यूनिसेफ राज्य और जिला स्तर पर बेहतर प्रशिक्षक तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ये प्रशिक्षक तमाम राज्यों में ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे हैं।

प्रशिक्षण में रणनीतिक ढांचे को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए व्यावहारिक गतिविधियों पर जोर दिया गया है। प्रतिनिधियों को हर तरह के सत्र में बुलाया जाता है। जल संसाधनों के प्रबंधन से लेकर कचरा प्रबंधन से जुड़ी जानकारी वाले व्याख्यानों तक, तमाम आयोजनों में उन्हें बुलाया जाता है। साथ ही, यह भी बताया जाता है कि स्वच्छाग्रहियों, राजमिस्त्री और अन्य स्थानीय समूहों को जोड़कर किस तरह से स्वच्छता चक्र के अगले अभियान को कैसे बढ़ावा दिया जाए। सफाई के संदेश को भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाता है जैसे – साबुन से हाथ धोना आदि। कम खर्च वाली यह आदत है। इसतरह डायरिया जैसी बीमारियों के बोझ को कम किया जा सकता है।

इन प्रयासों के परिणाम का इंतजार है। इससे यह भी पता चलेगा कि भारत सरकार के अगले चरण के अभियान में ये प्रयास किस तरह से योगदान करेंगे। हालांकि, अभी भी कई चीजे सीखना बाकी है। फलस्वरूप, मासिक धर्म से जुड़े कचरे का प्रबंधन, बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान और गड्ढे वाले शौचालयों को टिकाऊ और काम के लायक बनाने के लिए उनमें नई सुविधाएं जोड़ना। इन समस्याओं से असरदार ढंग से तभी निपटा जा सकता है, जब ग्राम पंचायतों को पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। इस स्तर पर नेतृत्व को सक्रिय किया जाए। दरअसल, लोगों की जिंदगी में दीर्घकालिक बदलाव लाने की ताकत उनके पास ही है।

मन, वाणी, कर्म, शरीर, हृदय, धर्म से लेकर विज्ञान तक में स्वच्छता का विशेष महत्व है। चेतना के उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता प्रथम सोपान है।

केन्द्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता की ओर उन्मुख किया है। स्वच्छता को जिन्दगी का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वच्छता और पेयजल मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को जोड़ दिया गया है। आयुष मंत्रालय से भी सहयोग लिया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण, मिशन इंद्रधनुष के तहत दूरदराज वाले इलाकों में टीकाकरण, राष्ट्रीय पोषण अभियान और आयुष्मान भारत जैसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं गरीब का बीमारी पर होने वाला खर्च कम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से तीन लाख बच्चों का जीवन बचने की संभावना पैदा हुई है। नवजात बच्चों का जीवन बचाने से जुड़े आंकड़े हों या फिर प्रसूता माताओं के, देश बहुत तेजी के साथ स्वस्थ भारत बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

स्वच्छता की पहल विकास की धारा को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होगी। इससे सामाजिक परिवर्तन की स्थिति बनती है जो मील का पत्थर साबित हो सकता है।

स्वच्छता को विकास से सीधे जोड़ने की जरूरत है और इस विकास को सीधे तौर पर सामाजिक परिवर्तन से जोड़कर देखा जाना चाहिए।

स्वच्छता मानव की एक आदर्श जीवनशैली है, इस विचार और धारणा को भारत में अभी दृढ़ता के साथ स्थापित करने की आवश्यकता है। हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है। गंदगी साफ करने वाला नीच या छोटा है, ऐसी सोच मानवता के प्रति एक बड़ा अक्षम्य अपराध है।

संदर्भ सूची

1. अरूण जेटली, स्वच्छता में निवेश का अर्थशास्त्र, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर, 2017
2. वी.श्रीनिवास, स्वच्छता सेवा ही अभियान, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर, 2017
3. स्वच्छता सर्वेक्षण 2017, कुरूक्षेत्र, सितंबर, 2017
4. स्वच्छता पर विशेष ध्यान, कुरूक्षेत्र, जनवरी, 2018
5. ऑपरेशन मलयुद्ध खुले में शौच मुक्त हरदा का सपना हुआ साकार, कुरूक्षेत्र, अगस्त, 2016
6. हरि विश्नोई, स्वच्छता दूत बने बुजुर्गों ने कायम की मिसाल, कुरूक्षेत्र, जनवरी, 2021